राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जनएम बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन1999 /4107

डाक पंजीयन-मप्र। भोपाल। 371 /20-2022

वर्ष-23,अंक-04(अट्ठाईस सालों से प्रकाशित) भोपाल,28जनवरी,शुक्रवार 2022 पेज-8,मूल्य पांच रुपया मात्र

कुंडलपुर में पंच कल्याणक महोत्सव 12 फरवरी से

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और संघ से जुड़े हजारों मुनिश्री और साधुगणों का महाकुंभ

भोपाल,25 जनवरी(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)दमोह जिले के विश्वप्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में सदी का सबसे बड़ा जैन साधु समागम होने जा रहा है। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक नगरी कुंडलपुर में पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव 12 फरवरी से शुरू होगा। आचार्यश्री विद्यासागर महाराज ने पहली बार हो रहे 11 दिवसीय पंचकल्याणक महोत्सव की कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद की यह घोषणा की। दुनिया के सबसे ऊंचे जैन मंदिर के इस लोकार्पण समारोह और पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव में आचार्यश्री के संघस्थ ढाई सौ से अधिक मुनि और आर्यिकाओं का सान्निध्य मिलेगा। 22 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में देशभर से 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। 200 से अधिक मुनि संघ कुंडलपुर में पहले से मौजूद हैं, कुछ मुनि संघों का कुंडलपुर की ओर विहार जारी है। पहले यह आयोजन 5 फरवरी से होना था, लेकिन कोरोना केस बढऩे के चलते इसे टाल दिया। अब कोरोना केसों में गिरावट और आचार्यश्री की सहमति

के बाद कुंडलपुर कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंघई ने यह जानकारी दी।

मुनि सेवा समिति के मुकेश जैन ढाना ने बताया कि 5 दिसंबर को आचार्यश्री का कुंडलपुर में प्रवेश हुआ। उसके बाद निर्यापक मुनि समयसागर, निर्यापक मुनि योगसागर, मुनि प्रशांतसागर, मुनि विमलसागर, अजितसागर, सौम्यसागर सहित कई अन्य संघ कुंडलपुर पहुंच चुके हैं। जिले के इसरवारा में जन्मे चतुर्थ निर्यापक मुनि सुधासागर भी 8 वर्ष बाद कुंडलपुर पहुंच रहे हैं।

189 फीट ऊंचाई, सिर्फ पत्थरों से काम

दमोह जिला मुख्यालय से 36 किमी दूर स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में बड़े बाबा के मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसके शिखर की ऊंचाई 189 फीट है। दुनिया में अब तक नागर शैली में इतनी ऊंचाई वाला मंदिर नहीं है। मंदिर की ड्राइंग डिजाइन अक्षरधाम मंदिर की डिजाइन बनाने वाले सोमपुरा बंधुओं ने तैयार की है। मंदिर की खासियत है कि इसमें लोहा, सरिया और सीमेंट का उपयोग नहीं किया है। इसे गुजरात व राजस्थान के लालपीले पत्थरों से तराशा गया है। पत्थर को दूसरे पत्थर से जोडऩे के लिए भी खास तकनीक का इस्तेमाल किया है।

63 मंदिर हैं स्थापित

प्राचीन स्थान कुंडलपुर को सिद्धक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहां 68मंदिर हैं, जो 5वीं-6वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। क्षेत्र 2500 साल पुराना बताया जाता है। कुण्डलपुर सिद्ध क्षेत्र अंतिम श्रुत केवली श्रीधर केवली की मोक्ष स्थली है। यहां 1500 वर्ष पुरानी पद्मासन श्री 1008 आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, जिन्हें बड़ेबाबा कहते हैं।

आचार्यश्री विद्यासागर जी की प्रेरणा से पहल

गजरथ महोत्सव और महामस्तकाभिषेक 2022 के संबंध में पदाधिकारियों ने बताया कि आचार्य विद्यासागर की प्रेरणा और पहल से हो रहे पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव के लिए आवश्यक अधो-संरचनात्मक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित की जा रही है। आयोजन समिति के साथ ही सभी संबंधित विभाग महोत्सव के लिए सुरक्षा, विद्युत, पेयजल, यातायात और अन्य सुविधाएँ विकसित कर रहे हैं। महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर रेल परिवहन व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार से भी अनुरोध किया जाएगा।

कुंडलपुर का महत्व

कुंडलपुर देश-विदेश के प्रमुख जैन तीर्थों में शामिल है। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व भगवान महावीर स्वामी का समवसरण यहां आया था। आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि सुधासागर महाराज का विहार चांदखेड़ी राजस्थान से गुरु चरणों की ओर कुंडलपुर के लिए चल रहा है। उनके 7 फरवरी को कुंडलपुर पहुंचने की संभावना है। मुनि सुधासागर महाराज ने जिज्ञासा समाधान में कहा कि भगवान महावीर स्वामी के बाद आचार्य भद्रबाहु स्वामी के संबंध में आगम में यह बात मिलती है कि पाटलीपुत्र में लगभग 24 हजार साधु इकट्ठा हुए थे और उसके 2000 साल बाद आचार्य कुंदकुंद स्वामी के संबंध में भी कथन है कि भगवान नेमिनाथ की निर्वाण भूमि गिरनार मे भी लगभग 500 साधु एकत्रित हुए थे। अब 2000 वर्ष बाद यह पहला इतिहास है जब कुंडलपुर में गुरुदेव विद्यासागर महाराज के मंगल सान्निध्य में इतने साधु इकटठे हो रहे हैं। मुनिश्री ने कहा कि जो जगत के आराध्य हैं वह गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं और उनके आराध्य कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं। गुरुदेव ने कहा इस करोना काल में भी हम सब इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे नसीब में कुंडलपुर के बड़े बाबा का पंचकल्याणक देखना लिखा है। ढाई हजार साल पहले कुंडलगिरी आया था महावीर स्वामी का समवसरण तो नाम पड़ गया कुंडलपुर कुंडलपुर के ट्रस्टियों की माने तो भगवान महावीर के 500 शिष्य हुए जिनमें इंद्रभूति गौतम के भट्टारक ने भ्रमण किया था। भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति ने कुंडलगिरी क्षेत्र से भगवान आदिनाथ की प्रतिमा खोजी थी। तब से यह माना जा रहा है कि भगवान महावीर का समवसरण 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुंडलपुर आया था। इस इलाके की पहाडिय़ां कुंडली आकार में होने के कारण पहले इसका नाम कुंडलगिरी था। बाद में धीरे-धीरे इसका नामकरण कुंडलपुर पड़ गया। जो अब सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यह क्षेत्र 2500 साल पुराना बताया जाता है। प्रतिमा के संदर्भ में यह कथा भी प्रचलित वैसे तो कुंडलपुर में विराजित भगवान आदिनाथ की 15 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की खोज करने वाले के रूप में भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति का नाम आता है। लेकिन एक किवदंती यह भी है कि पटेरा गांव में एक व्यापारी प्रतिदिन सामान बेचने के लिए पहाड़ी के दूसरी ओर जाता था। रास्ते में उसे प्रतिदिन एक पत्थर से ठोकर लगती थी। एक दिन उसने मन बनाया कि वह उस पत्थर को हटा देगा। लेकिन उसी रात उसे स्वप्न आया कि वह पत्थर नहीं तीर्थंकर मूर्ति है। स्वप्न में उससे मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने के लिए कहा गया, लेकिन शर्त थी कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसने दूसरे दिन वैसा ही किया। बैलगाड़ी पर मूर्ति सरलता से आ गई। जैसे ही आगे बढ़ा उसे संगीत और वाद्य, ध्वनियां सुनाई दीं। जिस पर उत्साहित होकर उसने पीछे मुड़कर देख लिया। और मूर्ति वहीं स्थापित हो गई। जिसके बाद उसने यही प्रतिमा स्थापित कराकर मंदिर बनवाया था।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
जासूस बादशाह
भोपाल,28जनवरी,शुक्रवार 2022

हिंदुत्व की नींव पर ही खड़ा होगा आत्मनिर्भर भारत

हिंदुस्तान की आम जनता ने भाजपा की मोदी सरकार को सत्ता में भेजकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था, अब तक भाजपा के तमाम क्षेत्रीय दिग्गज भी इसे समझने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले उन्नीस सालों से चूं चूं का मुरब्बा विचारधारा की लकीर पीट रही है। उमा भारती की जिस सरकार ने 2003 में सत्ता हासिल की थी वो तो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अनुसंधानों को लागू करने का प्रयास कर रही थी लेकिन उसके बाद प्रमोद महाजन ने इस सरकार का मुख्यमंत्री बदलकर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार भेजी उसने कांग्रेस की कर्ज आधारित अर्थ व्यवस्था की पैरवी शुरु कर दी। बिजली, सड़क और पानी के ऊंचे लक्ष्य बगैर पूंजी के संभव भी नहीं थे। पूंजी का उत्पादन जब होता तब होता लेकिन जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भाजपा की सरकार को बहुत पूंजी की जरूरत थी। तत्कालीन वित्तमंत्री राघवजी भाई ने अपनी अंकेक्षीय कुशलता के सुदीर्घ अनुभवों का लाभ देते हुए प्रदेश की बैलेंस शीट सुधारने का महारथ कर दिखाया। बढ़ी आय की वजह से धड़ाधड़ कर्ज स्वीकृत होते चले गए। सरकार को सड़कों का विशाल नेटवर्क खड़ा करने के लिए जो रकम चाहिए थी वो आसानी से उपलब्ध होने लगी। बिजली खरीद और ढांचागत विकास के लिए जो धन चाहिए था वह भी मिल गया। जल योजनाओं के लिए भी पर्याप्त पैसा होने की वजह से जनआकांक्षाओं के आकाशीय लक्ष्य आसानी से पूरे होते चले गए। शुरुआती वर्षों में शिवराज सिंह चौहान वाहवाही के कीर्तिमान खड़े करते चले गए। इसकी वजह थी कि कर्ज मिलता जा रहा था और उसे अन्य खातों में भेजकर जनता को खुश करने वाली योजनाएं आसानी से बनाई जा रहीं थीं। बाद में राघवजी भाई ने वाहवाही लूटने की इन योजनाओं पर लगाम लगानी शुरु कर दी। नतीजा नाराजगी लेकर आया। कांग्रेस से नजदीकी रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने अपने शिष्य शिवराज सिंह चौहान से राघवजी भाई की चरित्र हत्या करवाकर उन्हें रास्ते से हटा दिया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जयंत मलैया को वित्तमंत्री बनाया लेकिन वे आय और व्यय का संतुलन नहीं बना सके। नतीजतन प्रदेश की आय घटती चली गई। लोकप्रियता बटोरने वाली योजनाओं के लिए धड़ाधड़ कर्ज लिया जाने लगा। जिसकी वजह से ब्याज का पहाड़ खड़ा हो गया। बाजार से लिया गया ये कर्ज इतनी अधिक ब्याज दर पर था कि आज हर महीने लगभग पूरी आय ब्याज चुकाने में ही खर्च हो रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष तक भाजपा सरकारों ने लगभग तीन लाख करोड़ रुपयों का कर्ज लिया है। ये राशि बिजली सड़क पानी पर तो खर्च हो रही है लेकिन इससे उत्पादकता नहीं बढ़ पाई है। खेती की उत्पादकता जरूर बढ़ी है लेकिन इससे होने वाली आय नहीं बढ़ी है। खाद्यान्न खरीदी के लिए सरकार जो राशि खर्च करती है उसके बराबर भी आय कृषि से नहीं हो पाती है। ऐसे में जब कर्ज पटाना ही मुश्किल हो रहा हो तब विकास की नई परिभाषा कैसे रची जा सकती है। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनावों में कमलनाथ कांग्रेस की कलाकारी की राजनीति ने चुनाव नतीजों का पेंच फंसा दिया था। भाजपा को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। कमलनाथ ने जिस इंस्पेक्टर राज का दुहराव शुरु कर दिया था और लूट की राजनीति शुरु कर दी थी उसने सारे आर्थिक सुधारों की कमर तोड़ दी थी। नतीजतन युवा अर्थशास्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्गी कमलनाथ की जुगलबंदी वाली लुटेरी सरकार को गिराया और दुबारा भाजपा को सत्तासीन किया। इतना बड़ा धक्का खाकर सत्ता में लौटी शिवराज सिंह चौहान की सरकार इन हालात को भी समझने तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को मुगालता है कि उनकी लोकप्रियता वाली योजनाओं की वजह से ही प्रदेश में भाजपा का शासन फलफूल रहा है। जबकि ये कोरा ख्वाब है। संघ और भाजपा में घुसपैठ बना चुके फोकटियों को सत्ता की मलाई चंटवाकर चौहान अपनी भाजपा को अजेय समझ रहे हैं जबकि उनकी सरकार कांग्रेस की पिछलग्गू सरकार से अधिक साबित नहीं हो सकी है। देश में हिंदुत्व की जिस ललकार की अलख उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जलाई है उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। कांग्रेसी उस हिंदुत्व को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं जबकि गोरखपुर के मुसलमान बरसों से योगी की शैली को करीब से देख रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के इस दुष्प्रचार को ठेंगा दिखा दिया है। इस्लाम में अल्लाह को एक माना जाता है और जो उसे नहीं मानता उसे काफिर कहकर उसका सर कलम करने का फतवा दिया जाने लगता है। जबकि हिंदुत्व हर विचारधारा को मान्यता देता है। हिंदुओं के कभी तैंतीस करोड़ देवता होते थे आज सवा सौ करोड़ हैं। इससे किसी भी हिंदू को कोई गुरेज नहीं। यहां तक कि इस्लाम से भी किसी हिंदू को ऐतराज नहीं लेकिन जब उन पर इस्लाम थोपा जाने लगे तो जरूर वे प्रतिक्रिया देते हैं।इसकी वजह है कि हिंदुत्व कभी शैतान पर कंकर फेंककर अपना समय खराब करने की सलाह नहीं देता। कांग्रेसऔर हिंदुत्व की सोच में यही मूल अंतर है। इसके बावजूद शिवराज सरकार तो मुस्लिम कट्टरपंथियों तक को मक्खन खिलाने में जुटी हुई है। वोट की राजनीति की वजह से वह पूंजी निर्माण की सकारात्मक सोच से भटक रही है। उसे अपनी इस गलती का सुधार करना ही पड़ेगा नहीं तो पिछले चुनाव की परिपाटी इस बार भी उसका सुख चैन छीन लेगी।बुराईयों के बावजूद भाजपा का ये पतन जनताके लिए मंहगा सौदा साबित होगा।

ऋण गारंटी योजना ने दी बाजार को ताकत

प्रहलाद सबनानी

कोरोना महामारी के प्रथम दौर के काल में केंद्र सरकार द्वारा मई 2020 में आपात ऋण गारंटी योजना को प्रारम्भ किया गया था जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा एमएसएमई इकाईयों को प्रदान किए जाने वाले आपात ऋण की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों की समीक्षा करने पर यह पाया है कि आत्म निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लाई गई आपात ऋण गारंटी योजना ने लाखों सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्यमों तथा छोटे छोटे व्यापारियों को डूबने से बचा लिया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी उक्त प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इस योजना द्वारा न केवल 13.5 लाख एमएसएमई इकाईयों को कोरोना महामारी के दौर में बंद होने से बचाया गया है बल्कि 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने से भी बचा लिया है। इसी प्रकार एमएसएमई के 1.8 लाख करोड़ रुपए की राशि के खातों को विभिन्न बैंकों में गैर निष्पादनकारी आस्तियों में परिवर्तित होने से भी बचा लिया गया है। उक्त राशि एमएसएमई इकाईयों को प्रदान किए गए कुल ऋण का 14 प्रतिशत है। ज्ञातव्य हो कि कोरोना महामारी की प्रथम लहर के दौरान विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4.5 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण गारंटी योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान की गई कुल ऋणराशि में से 93.7 फीसदी राशि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों को प्रदान की गई है। छोटे व्यवसायी (किराना दुकान-दारों सहित), फुड प्रोसेसिंग इकाईयों एवं कपड़ा निर्माण इकाईयों को भी इस योजना का सबसे अधिक लाभ मिला है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश ने इस योजना का सबसे अधिक लाभ उठाया है। आपात ऋण गारंटी योजना को मई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। एमएसएमई इकाईयों एवं व्यवसायियों, जिन्होंने बैंकों से 50 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया हुआ था, को उनके द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही बैंक ऋण राशि का 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त की गई आपात गारंटी के अंतर्गत प्रदान किया गया था ताकि वे कोरोना महामारी की मार से ग्रसित अपने व्यावसायिक इकाई को उबार सकें। अगस्त 2020 में इस योजना का लाभ मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों एवं व्यापार करने के उद्देश्य से प्रदान किए व्यक्तिगत ऋणों को भी उपलब्ध कराया गया था। उक्त योजना की सफलता को देखते हुए नवम्बर 2020 में इस योजना का लाभ कामथ कमेटी द्वारा निर्धारित किए गए अर्थव्यवस्था के 26 अन्य क्षेत्रों की इकाईयों एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाईयों, जिन्हें बैंकों द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 500 करोड़ रुपए तक की ऋणराशि इस योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व ही स्वीकृत की गई थी, को भी उपलब्ध करा दिया गया था। मार्च 2021 में इस योजना का लाभ ट्रैवल एवं टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, खेल कूद एवं सिविल एवीएशन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत इकाईयों को उनके द्वारा 29 फरवरी 2020 के दिन में समस्त बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राशि का 40 प्रतिशत एवं अधिकतम 200 करोड़ रुपए की राशि तक उपलब्ध करा दिया गया था। इन इकाईयों को इस अतिरिक्त ऋणराशि को 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि को मिलाकर कुल 6 वर्षों में अदा करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान लागू किए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बहुत विपरीत रूप से प्रभावित हुए व्यापारियों एवं लघु उद्योग को बचाने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने उक्त योजना की घोषणा की थी। इस योजना के सफलता की कहानी उक्त वर्णित आंकड़े बयां कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों एवं सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों को इस योजना का बहुत अधिक लाभ मिला है। ऋण के रूप में प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता की राशि से इन उद्यमों को तबाह होने से बचा लिया गया है। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक की अवधि तक ही उपलब्ध रहेगा। प्रारम्भ में तो यह योजना एमएसएमई इकाईयों के लिए प्रारम्भ की गई थी परंतु बाद में छोटे व्यापारियों एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाईयों, आदि को भी इस योजना के दायरे में लाया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋणराशि की किश्तों को अदा करने के लिए एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि स्वीकृत की गई है अर्थात ऋण प्राप्त करने के एक वर्ष बाद ही ऋण के किश्तों की अदायगी प्रारम्भ होनी होती है एवं इसके बाद के तीन वर्षों में ब्याज सहित ऋण की अदायगी समान किश्तों में करनी होती है। अब छोटे छोटे व्यापारियों एवं एमएसएमई इकाईयों द्वारा यह मांग की जा रही है कि ब्याज सहित ऋण के किश्तों की अदायगी करने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इन इकाईयों के लिए अतिरिक्त कैश फ्लो तो बना नहीं है साथ ही किसी प्रकार की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी नहीं जोड़ी गई है, केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता को ही पुन: प्रारम्भ किया गया है। अत: बैंकों को छोटे व्यापारियों एवं एमएसएमई इकाईयों की इस मांग पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। उक्त योजना के लागू किए जाने से बैंकों को भी लाभ हुआ है क्योंकि समस्त बैंकों की गैर निष्पादनकारी आस्तियों में उक्त योजना के चलते बहुत कमी दृष्टिगोचर हुई है। उक्त योजना के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर लघु उद्योग एवं व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री मुद्रा ऋण योजना को अप्रेल 2015 में बैंकों के माध्यम से लागू किया गया था। उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों पर उधारकर्ता से प्रतिभूति नहीं ली जाती है अत: इस प्रकार के ऋण बैंकों से आसान शर्तों पर मिल जाते हैं। चूंकि आपात ऋण गारंटी योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगा अत: इस योजना की सफलता को देखते हुए इसके अच्छे बिंदुओं को बैंकों में पिछले लगभग दो दशकों से चल रही इसी प्रकार की सीजीटीएमएसई योजना में शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में सीजीटीएमएसई योजना का लाभ विभिन्न बैंकों द्वारा अपने बहुत कम हितग्राहियों को दिया जा रहा है। अत: इस विषय पर बहुत गम्भीर चिंतन करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा चालू की जा रही इस प्रकार की योजनाएं यदि सभी बैंकों द्वारा अच्छे तरीके से लागू की जाती हैं तो छोटे व्यवसाईयों एवं एमएसएमई इकाईयों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में आसानी होगी एवं इस प्रकार के ऋणों पर सरकार की अथवा सीजीटीएमएसई की गारंटी उपलब्ध रहेगी एवं बैंकों पर हितग्राहियों द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किए जाने के सम्बंध में जो लगातार दबाव बना रहता है, जिसके चलते कई बैंक तो छोटे छोटे व्यवसायियों एवं एमएसएमई इकाईयों को ऋण प्रदान करने से ही कतराते हैं, वह भी कम हो जाएगा।

प्रहलाद सबनानीकोरोना महामारी के प्रथम दौर के काल में केंद्र सरकार द्वारा मई 2020 में आपात ऋण गारंटी योजना को प्रारम्भ किया गया था जिसके अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा एमएसएमई इकाईयों को प्रदान किए जाने वाले आपात ऋण की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों की समीक्षा करने पर यह पाया है कि आत्म निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत लाई गई आपात ऋण गारंटी योजना ने लाखों सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्यमों तथा छोटे छोटे व्यापारियों को डूबने से बचा लिया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी उक्त प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इस योजना द्वारा न केवल 13.5 लाख एमएसएमई इकाईयों को कोरोना महामारी के दौर में बंद होने से बचाया गया है बल्कि 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने से भी बचा लिया है। इसी प्रकार एमएसएमई के 1.8 लाख करोड़ रुपए की राशि के खातों को विभिन्न बैंकों में गैर निष्पादनकारी आस्तियों में परिवर्तित होने से भी बचा लिया गया है। उक्त राशि एमएसएमई इकाईयों को प्रदान किए गए कुल ऋण का 14 प्रतिशत है। ज्ञातव्य हो कि कोरोना महामारी की प्रथम लहर के दौरान विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4.5 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण गारंटी योजना प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदान की गई कुल ऋणराशि में से 93.7 फीसदी राशि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों को प्रदान की गई है। छोटे व्यवसायी (किराना दुकान-दारों सहित), फुड प्रोसेसिंग इकाईयों एवं कपड़ा निर्माण इकाईयों को भी इस योजना का सबसे अधिक लाभ मिला है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश ने इस योजना का सबसे अधिक लाभ उठाया है। आपात ऋण गारंटी योजना को मई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। एमएसएमई इकाईयों एवं व्यवसायियों, जिन्होंने बैंकों से 50 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया हुआ था, को उनके द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही बैंक ऋण राशि का 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त की गई आपात गारंटी के अंतर्गत प्रदान किया गया था ताकि वे कोरोना महामारी की मार से ग्रसित अपने व्यावसायिक इकाई को उबार सकें। अगस्त 2020 में इस योजना का लाभ मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों एवं व्यापार करने के उद्देश्य से प्रदान किए व्यक्तिगत ऋणों को भी उपलब्ध कराया गया था। उक्त योजना की सफलता को देखते हुए नवम्बर 2020 में इस योजना का लाभ कामथ कमेटी द्वारा निर्धारित किए गए अर्थव्यवस्था के 26 अन्य क्षेत्रों की इकाईयों एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाईयों, जिन्हें बैंकों द्वारा 50 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 500 करोड़ रुपए तक की ऋणराशि इस योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व ही स्वीकृत की गई थी, को भी उपलब्ध करा दिया गया था। मार्च 2021 में इस योजना का लाभ ट्रैवल एवं टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, खेल कूद एवं सिविल एवीएशन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत इकाईयों को उनके द्वारा 29 फरवरी 2020 के दिन

(शेष भाग पेज छह पर पढ़िए)

यूपी को योगी से बेहतर सड़कें मुहैया कराने की उम्मीद

नितिन कुमार

सुशांत कुमार शर्मा दो मीटर चौड़े गंदे रास्ते पर जाने के लिए दाएं मुडऩे से पहले नए बने छह लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं। इस रास्ते से ही वह बाराबंकी जिले के अपने गांव रमीपुर तक जाएंगे जो लखनऊ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। शर्मा कहते हैं, 'यह एक्सप्रेसवे मेरे घर तक की यात्रा का सबसे दर्दनाक हिस्सा रहा है। जब 2020 में मुझे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान खाली हाथ वापस आना पड़ा था उस वक्त मुझे इस पर 30 किलोमीटर से भी अधिक चलना पड़ा '

वह कहते हैं, 'लेकिन अब मैं खुश हूं क्योंकि अब कम से कम मेरा गांव राज्य की राजधानी से जुड़ा हुआ है।' लेकिन फिर वह थोड़ी निराशा से कहते हैं, 'नौकरी खोजने के लिए शहरों की यात्रा करने के अलावा इस राजमार्ग का मेरे लिए क्या उपयोग है? इस एक्सप्रेसवे की वजह से अभी तक इस क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं आया है।' महामारी से पहले दिल्ली में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले शर्मा को अपने जिले में स्थायी नौकरी पाने में मुश्किल हो रही है। अब वह एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं और 10 घंटे की मजदूरी करके एक दिन में लगभग 100 रुपये कमाते हैं।

शर्मा अकेले नहीं हैं। 2020 में लॉकडाउन के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने गांवों में लौटने वाले कई प्रवासी श्रमिक अपने गांवों में और उसके आसपास नौकरी पाने में विफल रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रोजगार देने का प्रमुख जरिया रहा है और यह आगे

भी रहेगा जिसका उद्घाटन पिछले साल 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

इसने एक्सप्रेसवे के साथ नौ जिलों में कई औद्योगिक विकास परियोजनाओं की सूची भी बनाई है। इनमें कपड़ा कारखानों, बेवरिज इकाइयों से लेकर दवा और बिजली के उपकरण के कारखानों तक शामिल हैं। सरकार बाराबंकी और अयोध्या जिलों में खाद्य, लकड़ी और दवा उद्योगों को भी लगाने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि बिहार को भी फायदा होगा। इससे दिल्ली और गोरखपुर के बीच यात्रा के समय में भी कमी आएगी।' हालांकि आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके बाराबंकी की जमीनी हकीकत सरकार के इस दावे से बिल्कुल अलग है कि एक्सप्रेसवे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार लेकर आया है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा लोगों के प्रवास से जुड़े कार्यसमूह की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 25 प्रतिशत अंतरराज्यीय स्थानांतरण 17 जिलों से हो रहा है और इनमें से 10 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। अयोध्या जिले के गोंडवा गांव के सोमबीर सिंह कहते हैं, 'मेरे पास दो बीघा खेत है। हम जो भी उगाते हैं वही खाते हैं। बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए, मैं एक मजदूर के रूप में काम करता हूं।' पूर्वी उत्तर प्रदेश में देश में एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि जोत का उच्चतम प्रतिशत (84 प्रतिशत से अधिक) है। जमीन के छोटे रकबे के अलावा सालाना स्तर पर आने वाली बाढ़ से भी किसानों की परेशानी बढ़ जाती है।

घाघरा, राप्ती, कुवानो और सरयू जैसी नदियों से बाढ़ का पानी हर साल 30,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन की फसलों को बहा ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुमानों के अनुसार हर साल 20 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ चुके 23 साल के समर्थ सिंह कहते हैं, 'यहां किसी को काम नहीं मिलता है। कोई कारखाने, आवासीय सोसायटी और पत्थर खदानें नहीं हैं जहां हम काम कर सकते हैं। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का 'शान' और 'कमाल' कहा था और इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की 'जीवन रेखा' भी कहा था। लेकिन वास्तव में, यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रेखा है और यहां कोई बेहतर जीवन और गर्व का अनुभव नहीं है। हर साल बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग मर जाते हैं और हजारों लोग अपने घरों और फसलों को गंवा देते हैं। यह गर्व की बात कैसे है?'

लेकिन यहां ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य महामारी के दौरान बड़े पैमाने पर हुआ था और इसने न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार दिया बल्कि उन लोगों को भी रोजगार दिया जो लॉकडाउन के दौरान शहरों से वापस घर लौटे थे। निर्माण कार्य से जुड़े एक मजदूर राम पाल कहते हैं, 'मैंने इस एक्सप्रेसवे पर दो साल से अधिक समय तक काम किया है। इस सड़क की वजह से मुझे अभी तक काम की तलाश नहीं करनी पड़ी है। मुझे विश्वास है कि इसका काम पूरा होने के बाद भी मुझे काम मिलेगा क्योंकि सरकार के पास हमारे क्षेत्र में पर्याप्त परियोजनाएं चल रही हैं।' स्थानीय लोगों से पूछने पर कई लोग कहते हैं कि वे इस बात को लेकर खुश हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है लेकिन उन्हें इन योजनाओं और परियोजनाओं के पूरा होने की रफ्तार को लेकर संदेह है। एक घरेलू महिला पूनम देवी कहती हैं, 'सरकार हमारे लिए काम कर रही है लेकिन उसे समय पर काम करना चाहिए। बहुत सारी परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं और उन पर अब भी काम होना है। उन्हें उन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।'जनता को भरोसा है बेहतर सड़कें जल्दी उपलब्ध होगी।

विकास से महरूम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लगे इलाके

नितिन कुमार

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुडऩे वाले बांदा-महोबा राजमार्ग के किनारे पानी की 50 लीटर का कैन ले जा रही 20 साल की सरिता देवी काफी थकी हुई लग रही हैं। वह कहती हैं, 'मेरी दादी गंदगी से भरे रास्ते से पानी ले जाती थीं, मेरी मां दो लेन वाली सड़क के रास्ते पानी ले जाती थीं और अब मैं चार लेन के राजमार्ग से पानी ले जा रही हूं। पिछले 70 वर्षों में कई चीजें बदल गई हैं लेकिन हमारे लिए अब भी बहुत कुछ पहले जैसा ही है।' उन्हें अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर एक कुएं से पानी लाना पड़ता है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम मार्च-अप्रैल 2022 तक पूरा किया जाना है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिलों को कवर करता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर कहा गया कि इससे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी और पीने योग्य पर्याप्त पानी भी उपलब्ध होगा।

जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 2.64 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 34 लाख के पास ही नल का पानी है और इस लिहाज से यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। मंत्रालय ने 2024 तक हर भारतीयों के घर में नल का पानी लाने की योजना बनाई है। बुंदेलखंड के लोग सिर्फ पानी के लिए ही नहीं तरस रहे हैं। वे बुनियादी ढांचे के विकास और नौकरियों की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

झांसी जिले में किसान से उद्योग में काम करने वाले मजदूर बने संजय तिवारी कहते हैं, 'यह रानी लक्ष्मीबाई की जमीन है जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। दुर्भाग्यवश, बुंदेलखंड के लोग अभी भी अन्य राज्यों में औद्योगिक श्रमिकों के रूप में गुलामी कर रहे हैं क्योंकि यहां कोई काम नहीं है।' राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए 2018 में उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया जिसके बाद तिवारी ने एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यह गलियारा झांसी से चित्रकूट तक फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इसको सहूलियत मिली हुई है इसका मकसद 20,000 करोड़ रुपये का निवेश लाना और क्षेत्र में 250,000 रोजगार के मौके तैयार करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि गलियारे का काम पूरा किया जाना बाकी है।

तिवारी कहते हैं, 'उन्होंने नौकरियों का वादा करके हजारों एकड़ जमीन लूट ली। लेकिन अब कई साल हो गए हैं और यहां कोई भी उद्योग नहीं लगा है।' अधिकांश स्थानीय लोग तिवारी की बात पर हामी भरते हुए कहते हैं कि सरकार हर जगह सिर्फ आधारशिला रख रही है और इसने शायद ही कोई उद्घाटन किया हो। बुंदेलखंड के एक अन्य निवासी कहते हैं, 'झांसी और चित्रकूट अब भी अपने स्मार्ट शहरों, सौर संयंत्रों और मंडियों की तलाश में हैं।'

राज्य में निवेश और नौकरियों पर एक्सप्रेसवे के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल को टाल दिया और कहा, 'उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लाभ उठाएंगे। इससे इन सभी राज्यों की राष्ट्रीय राजधानी के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी।'

बुंदेलखंड के एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने वाले करण सिंह का मानना है कि बुनियादी ढांचे के अलावा, सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अपराध खत्म करने जैसे क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त रूप से काम नहीं कर रही है।

सिंह पूछते हैं, 'नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अपराध दर अब तक सबसे अधिक है। इसके अलावा, 23 करोड़ की आबादी के लिए हमारे पास केवल 77 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। सरकार इन मानकों में सुधार के लिए कुछ भी क्यों नहीं कर रही है?

अगर कोई आंकड़ों को ध्यान से देखता है तो बुंदेलखंड इन सभी मापदंडों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है।' हालांकि, हर किसी को नहीं लगता कि बुंदेलखंड में सब कुछ बुरा है। हालांकि रक्षा औद्योगिक गलियारे की घोषणा के बाद से इस क्षेत्र में कोई बड़ा विनिर्माण उद्योग नहीं आया है लेकिन कम से कम एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के करीब है। करण सिंह के पिता 70 वर्षीय दान सिंह कहते हैं, 'भयंकर सूखा पडऩे और चंबल की घाटियों के चारों ओर डाकुओं के घूमने की वजह से बुंदेलखंड को खराब जगह माना जाता है। अब, इन एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के आने की वजह से हम अपने जीवन में पहली बार राहत महसूस कर रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी इन बुनियादी ढांचे के विकास का लाभ उठाएगी।'

इसी तरह, कई लोग नरेंद्र मोदी सरकार के 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने के वादे से खुश हैं। लेकिन उन्हें इस बात पर संशय जरूर है कि निर्धारित समय में लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा या नहीं। सरिता देवी कहती हैं, 'मुझे खुशी है कि सरकार ने दूर जाकर पानी लाने की मुश्किलों से मुक्त करने के लिए एक समय सीमा तय की है, लेकिन ऐसा जब हो जाएगा तभी माना जा सकता है।'फिर भी उन्हें योगी सरकार पर भरोसा है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया स्थायित्व बोले मोदी

लखनऊ,(प्रेस इंफारमेशन सेंटर)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनचौपाल में विपक्षी दलों पर हमला बोलने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता काफी समझदार है। यह परखने के बाद ही किसी भी विश्वास करती है। लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में वर्चुअल प्रचार का मोर्चा बखूबी संभाल लिया है। उत्तराखंड और पंजाब के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के साथ प्रत्याशियों को भी संबोधित किया। उन्होंने संभल, बदायूं और रामपुर के मतदाताओं को संबोधित किया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांचवीं जनचौपाल थी। इन तीनों जिलों में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण के मतदान वाले तीन अन्य जिलों के मतदाताओं को पीएम मोदी ने सोमवार को संबोधित किया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनचौपाल में विपक्षी दलों पर हमला बोलने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता काफी समझदार है। यह परखने के बाद ही किसी भी विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि यूपी परखता सबको है, लेकिन विश्वास उसी को देता है, जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। यह लोग प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले अनेक साल विकल्पों की तलाश में रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संभल, रामपुर और बदायूं की 15 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जन चौपाल रैली को संबोधित किया। वर्चुअल जन चौपाल में कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे बदायूं के किसानों और नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल बनाएगा। यह जिला सोलर एनर्जी का प्रमुख केंद्र बन रहा है। दातागंज का प्लांट बड़े क्षेत्र को रोशन कर रहा है। एथेनाल प्लांट का काम भी यहां चल रहा, जिससे किसानों और नौजवानों के सपने साकार होंगे। हर घर नल से जल के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। गरीबों को पक्का मकान, उज्ज्वला गैस योजना की चर्चा करते हुए भाजपा के उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा।

बदायूं, सम्भल और रामपुर के लोगों से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली समाजवादी छोटे-छोटे विकास काम के लिए कितना तरसाते थे, यह बात लोग नहीं भूल सकते। उत्तर प्रदेश के लोग राजनीति के जानकार तो हैं ही, सच्चाई की अच्छी परख भी रखते हैं। परखते सभी को हैं लेकिन, विश्वास उसी पर करते जो उम्मीदों पर खरा उतरता है। तीन तलाक कानून के लिए कहा कि अब मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का एहसास होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस कानून से महिलाएं तो खुश हैं मगर पुरुष नाराज हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि तीन तलाक के बाद बेटी अचानक घर आती है तो मां-बाप, भाई को तकलीफ नहीं होती? यह कानून बनाकर मां-बाप, भाइयों को आश्वस्त किया है। मैंने वोट की चिंता नहीं की है, जन कल्याण के लिए काम किया है।

गांवों में स्वरोजगार पर कहा कि दूध के साथ गोबर को भी किसानों की आमदनी का माध्यम बनाया जा रहा है। गोबर से लाभ मिलेगा तो पशु कभी बोझ नहीं लगेगा। विपक्षी दलों पर निशाना साधा कि वे लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए खेल कर रहे। उम्मीदवारों के नाम पढ़कर पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है। इन दलों के प्रत्याशी हिस्ट्रीशीटर हैं या दंगावादी। वोट डालने से पहले इनकी करतूत मत भूलना। इनको सिर्फ कुर्सी का मोह नहीं है, बदला लेने की फिराक में हैं। गलती से मौका मिल गया तो खेत लहूलुहान हो जाएगा, फिर दुकानें जलेंगी।

भाजपा के घोषणा पत्र का मतलब समझाते हुए कहा कि यह संकल्प पत्र बीते पांच साल की सिद्धियों से प्रेरित है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से गांव के घरों, गांव की संपत्ति के कानूनी दस्तावेज दिए जा रहे हैं। घरौनी की चर्चा करते हुए कहा कि अब कोई माफिया किसी के घर और जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी बेला में जनता योगी की नीतियों से सहमत होती दिखाई दे रही है।

भारत की राजनीतिक दिशा तय करेंगे उपचुनाव के मुद्दे

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव कुछ प्रमुख राजनीतिक सवाल उठाएंगे, जिनकी गूंज पूरे देश में होगी। इन विधानसभा चुनावों के कम से कम छह परिभाषित मुद्दे हैं।

मैदान की रक्षा कर रही कांग्रेस, भाजपा: दो राष्ट्रीय दल इस बार अपने एक प्रमुख मैदान का बचाव कर रहे हैं- उत्तर प्रदेश में भाजपा और पंजाब में कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस की योजनाओं में क्रमशः उत्तर प्रदेश और पंजाब के महत्व को समझने के लिए, इन राज्यों ने अपनी राष्ट्रीय ताकत में जो योगदान दिया है, उस पर ध्यान दें। कांग्रेस की 52 लोकसभा सीटों में से ग्यारह – 20% – पंजाब से आती हैं। बीजेपी की 301 लोकसभा सीटों में से 62 यानी 20 फीसदी उत्तर प्रदेश से आती हैं. हालांकि, बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे का सामना नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करते हैं। दोनों ही राज्यों में विपक्ष की चाल चल रही है। समाजवादी पार्टी (सपा) उत्तर प्रदेश में भीड़ खींच रही है, और आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में एक चर्चा का विषय है, लेकिन शुरुआत में सत्ताधारियों का हाथ है।

अल्पसंख्यक समस्या : भाजपा व्यावहारिक रूप से पंजाब में न के बराबर है; और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है- जो एक मौलिक संघर्ष को दर्शाता है जिसका इन राष्ट्रीय दलों का सामना करना पड़ता है। भाजपा पर धार्मिक अल्पसंख्यकों का अविश्वास है, और सिखों को लुभाने के उसके प्रयास आधे-अधूरे हैं। यह आवास और शत्रुता के बीच झूलता है। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के सवाल पर बड़े पैमाने पर कृषक समुदाय सिखों के साथ पार्टी के टकराव ने इस बार अपनी अपील को और कम कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस को बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद पार्टी के रूप में देखा जाता है। पार्टी का गढ़ इन दिनों ऐसे क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां अल्पसंख्यकों की एक महत्वपूर्ण आबादी है, जो इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के स्थानों और स्थितियों में अव्यवहारिक बना देती है। भाजपा की अल्पसंख्यक समस्या यह है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है; कांग्रेस का यह है कि उसका आधार काफी हद तक अल्पसंख्यक क्षेत्रों तक ही सीमित है। भाजपा पंजाब में सिखों को पाकिस्तान में उनके पवित्र स्थलों की यात्रा को आसान बनाने जैसे उपायों के माध्यम से लुभाती रही है; यह शायद गोवा में कैथोलिकों से दोस्ती का संकेत देना चाहता था, जो कि जनसंख्या का एक तिहाई है, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पोंटिफ से मुलाकात की थी। पंजाब में पैर जमाना चाहती है भाजपा; कांग्रेस इन चुनावों के जरिए उत्तर प्रदेश में पैर जमाना चाहती है।

नेतृत्व के प्रश्न: यदि भाजपा उत्तर प्रदेश जीतती है, तो योगी आदित्यनाथ श्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभरेंगे। हाल के महीनों में उनका ब्रांड अभियान भारत के सबसे बड़े राज्य को बदलने वाले एक निर्दयी हिंदु नेता के रूप में उन्हें सुर्खियों में रखता है। पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों के विपरीत। श्री आदित्यनाथ पहले ही श्री मोदी की छाया के बाहर खुद को स्थापित कर चुके हैं। कांग्रेस में, प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी उत्तर प्रदेश की रणनीति के प्रभारी हैं; और उन्होंने पंजाब में पार्टी अध्यक्ष के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को चुना। पार्टी का प्रदर्शन उनके नेतृत्व कौशल को प्रतिबिंबित करेगा, और उनकी भूमिका पर आंतरिक बहस को प्रभावित करेगा।

परीक्षण में क्षेत्रीय राजनीति के दो मॉडल: उत्तर प्रदेश में सपा एक प्रभावशाली जाति के नेतृत्व वाली पिछड़ी राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है; पंजाब में शिरोमणि अकाली दल अल्पसंख्यक धार्मिक राजनीति करता है। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाओं के स्पेक्ट्रम में दो विशिष्ट मॉडल। दोनों एक संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पारंपरिक लामबंदी की रणनीतियाँ अब कमजोर हैं, और उनकी भ्रष्टाचार से ग्रस्त वंशवादी राजनीति मतदाताओं के लिए अस्वीकार्य है।

चौराहे पर दलित राजनीति कुछ साल पहले तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दबदबे वाले गढ़ में दलित राजनीति दोराहे पर है। उत्तर प्रदेश में पहले भी कई बार सत्ता में रही बसपा का पतन होता दिख रहा है। पंजाब में भी इसकी मजबूत उपस्थिति थी, हालांकि इसने कभी सत्ता हासिल नहीं की। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा की कीमत पर दलितों के बीच महत्वपूर्ण पैठ बनाई है। पंजाब में, दलितों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है, और पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी, एक दलित, को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के बाद उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन विधानसभा चुनावों के नतीजे कुछ संकेत दे सकते हैं कि यहां से दलित राजनीति कैसे विकसित होगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलितों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

भाजपा के लिए गैर-कांग्रेसी विकल्प की महत्वाकांक्षाएं: दो मुख्यमंत्री हैं जो अपनी राजनीति को अपने-अपने मौजूदा कार्यक्षेत्र से बाहर परख रहे हैं – दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी। दोनों 2024 से पहले श्री मोदी के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में उभरना चाहते हैं। श्री केजरीवाल का ध्यान पंजाब है जहां उनकी पार्टी 2017 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी; सुश्री बनर्जी गोवा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आप गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी है; टीएमसी मणिपुर में खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही है। इन दोनों नेताओं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं दो अलग-अलग मॉडलों और गणना के दो अलग-अलग सेटों पर आधारित हैं। इस बार उनका प्रदर्शन 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति के पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकता है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव कुछ प्रमुख राजनीतिक सवाल उठाएंगे, जिनकी गूंज पूरे देश में होगी। इन विधानसभा चुनावों के कम से कम छह परिभाषित मुद्दे हैं। यहाँ एक त्वरित लेना है।

मैदान की रक्षा कर रही कांग्रेस, भाजपा: दो राष्ट्रीय दल इस बार अपने एक प्रमुख मैदान का बचाव कर रहे हैं- उत्तर प्रदेश में भाजपा और पंजाब में कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस की योजनाओं में क्रमशः उत्तर प्रदेश और पंजाब के महत्व को समझने के लिए, इन राज्यों ने अपनी राष्ट्रीय ताकत में जो योगदान दिया है, उस पर ध्यान दें। कांग्रेस की 52 लोकसभा सीटों में से ग्यारह – 20% – पंजाब से आती हैं। बीजेपी की 301 लोकसभा सीटों में से 62 यानी 20 फीसदी उत्तर प्रदेश से आती हैं. हालांकि, बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे का सामना नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करते हैं। दोनों ही राज्यों में विपक्ष की चाल चल रही है। समाजवादी पार्टी (सपा) उत्तर प्रदेश में भीड़ खींच रही है, और आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में एक चर्चा का विषय है, लेकिन शुरुआत में सत्ताधारियों का हाथ है।

अल्पसंख्यक समस्या : भाजपा व्यावहारिक रूप से पंजाब में न के बराबर है; और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है- जो एक मौलिक संघर्ष को दर्शाता है जिसका इन राष्ट्रीय दलों का सामना करना पड़ता है। भाजपा पर धार्मिक अल्पसंख्यकों का अविश्वास है, और सिखों को लुभाने के उसके प्रयास आधे-अधूरे हैं। यह आवास और शत्रुता के बीच झूलता है। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के सवाल पर बड़े पैमाने पर कृषक समुदाय सिखों के साथ पार्टी के टकराव ने इस बार अपनी अपील को और कम कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस को बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद पार्टी के रूप में देखा जाता है। पार्टी का गढ़ इन दिनों ऐसे क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां अल्पसंख्यकों की एक महत्वपूर्ण आबादी है, जो इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के स्थानों और स्थितियों में अव्यवहारिक बना देती है। भाजपा की अल्पसंख्यक समस्या यह है कि उसे उस पर भरोसा नहीं है; कांग्रेस का यह है कि उसका आधार काफी हद तक अल्पसंख्यक क्षेत्रों तक ही सीमित है। भाजपा पंजाब में सिखों को पाकिस्तान में उनके पवित्र स्थलों की यात्रा को आसान बनाने जैसे उपायों के माध्यम से लुभाती रही है; यह शायद गोवा में कैथोलिकों से दोस्ती का संकेत देना चाहता था, जो कि जनसंख्या का एक तिहाई है, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पोंटिफ से मुलाकात की थी। पंजाब में पैर जमाना चाहती है भाजपा; कांग्रेस इन चुनावों के जरिए उत्तर प्रदेश में पैर जमाना चाहती है।

नेतृत्व के प्रश्न: यदि भाजपा उत्तर प्रदेश जीतती है, तो योगी आदित्यनाथ श्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभरेंगे। हाल के महीनों में उनका ब्रांड अभियान भारत के सबसे बड़े राज्य को बदलने वाले एक निर्दयी हिंदु नेता के रूप में उन्हें सुर्खियों में रखता है। पार्टी के अन्य

(शेष भाग पेज छह पर पढ़िए)

एनडीपीएस एक्ट से हत्यारी बन गई अफीम की खेती

नई दिल्ली/लखनऊ। सरकारी नियंत्रण में होने वाली अफीम की खेती कभी भारत के कई राज्यों में होती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्से में सिमटकर रह गई है। सरकार के मुताबिक अफीम का उपयोग सिर्फ औषधि निर्माण में होता है, इसलिए जरुरत के हिसाब से ही इसके लाइसेंस दिए जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने विदेश को निर्यात होने वाली अफीम पर रोक लगा दी है, इसका असर भी खेती पर पड़ा है। संसद में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि अफीम की खेती के लिए सरकार का मौजूदा नियम (मॉर्फिन प्रणाली) ही लागू रहेगी। अफीम की खेती और नियम पर सरकार ने संसद में कहा, "देश में अफीम की खेती संयुक्त राष्ट्र संघ के ड्रग मामलों संबंधी सम्मेलन और एनडीपीएस एक्ट 1985 के अनुसार अफीम और उसमें मौजूद उत्पाद अल्कलॉइड के चिकित्सा उपयोग के उद्देश्य से की जाती है। पहले अफीम गोंद का उपयोग घरेलू उपयोग के लिए एल्कलॉइड के निकालने के अलावा कई देशों में निर्यात के लिए भी किया जाता था, लेकिन अब आयातक देश अफीम गोंद के बजाए कॉन्सेन्ट्रेटर ऑफ पोस्ता स्ट्रॉ से एल्कलॉइड निकालकर अपनी चिकित्सा जरुरतें पूरी कर रहे हैं। इसलिए देश में अब अफीम का उत्पादन केवल देश की जरुरत (घरेलू उपयोग) के लिए ही किया जाता है। देश में अफीम की गोंद की अब जरूरत कम होती है। देश में अफीम का उत्पादन सिर्फ आवश्यकता पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी खेती का रकबा कम या ज्यादा भी होता रहता है।" लोकसभा में सरकार का जवाब संसद के शीतकालीन सत्र में राजस्थान में नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अफीम की खेती में पहले जो औसत उपज के आधार पर सरकार को अफीम देने का नियम था वो कम वैज्ञानिक था उसके बदले जो मार्फिन का नियम है वो ज्यादा वैज्ञानिक है, साथ ही इससे गुणवत्ता वाली मॉर्फिन (Morphine) मिलती है, इसलिए आगे भी यही नियम लागू रहेगा। देश में अगर अफीम की खेती की बात करें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2012-13 में मध्य प्रदेश में 3084 हेक्टेयर में, राजस्थान में 2529 हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 6 हेक्टेयर में अफीम की खेती हुई थी। जबकि साल 2015-16 के दौरान मध्य प्रदेश में 76 हेक्टेयर, राजस्थान में 477 और उत्तर प्रदेश में 4 हेक्टेयर में अफीम की खेती हुई थी। वहीं अगर साल 2021-22 के अनुमानित अनुमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2850, राजस्थान 3142 और उत्तर प्रदेश में 201 हेक्टेयर में अफीम की खेती हुई है। कुल उत्पादन की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा क्षेलफल की बात करें 2016-17 में 8712 हेक्टेयर और 2015-16 में सबसे कम 557 हेक्टेयर ही रकबा था। हालांकि पिछले 10 वर्षों में अपेक्षाकृत यूपी का रकबा बढ़ा है। वहीं अगर पूरे देश में अफीम के उत्पादन की बात करें तो सरकार के जवाब के मुताबिक साल 2016-17 में 560 टन रही जबकि 2017-18 में 280, 2018-19 में 405, 2019-20 में 287 और 2020-21 के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक 315 टन हुआ, (उपरोक्त सभी में उत्पादन में 70 सांद्रता है)। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में ही अगर विदेश से मंगाई गई कोडीन फॉस्फेट के आंकड़े देखे तो पता चलता है सरकारी कारखानों में आयतित कोडीन फॉस्फेट की मात्रा 2016-17 में शून्य किलोग्राम थी, जबकि 2017-18 में 15000 किलोग्राम, 2018-19 में 12500 किलो, 2019-20 में 20000 और 2020-21 में 11000 किलोग्राम था। अफीम की खेती भारत में पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होती है। इसलिए लाइसेंस जारी किया जाता है। खेत की इंच-इंच जमीन की नपाई होती है। सरकार जो मात्रा तय करती है, उतनी उसे हर हाल में देनी होती है। फसल बर्बाद होने पर वो मात्रा पूरी करनी होती इसलिए अलावा नारकोटिक औषधि और मनः प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत तमाम प्रावधानों का भी पालन करना होता है। किसान और सरकार के बीच इन्हीं नियमों को लेकर गतिरोध रहते हैं। 20 दिसंबर को लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार का विचार मॉर्फिन नियम को हटाने का है, और इसे राजस्थान समेत अन्य राज्यों में अफीम उत्पादक किसानों की औसत मांग पर पट्टे देने का है? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि अफीम की खेती ही चिकित्सा उद्देश्य के लिए एल्कलॉइड विशेष कर मार्फिन प्राप्त करने के लिए होती है, इसलिए किसान को दिए जाने वाले लाइसेंस में अफीम की मात्रा को मॉर्फिन में बदला गया है। अफीम की मात्रा मार्फिन से मापी जाती है लेकिन इसमें मानवीय दखल न्यूनतम होता है। औसत उपज पद्धति कम वैज्ञानिक थी, नए नियमों से गुणवत्ता में सुधार हुआ है इसलिए आगे भी यही नियम लागू रहेगा। अफीम की खेती के लिए सरकार हर साल अफीम पॉलिसी जारी करती है। 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर तक चलने वाली अफीम फसल वर्ष की खेती के लिए सरकार ने अक्टूबर महीने में पॉलिसी जारी की थी, जिसके उन किसानों को ही लाइसेंस मिलेगा, जिन्होंने 2020-21 अफीम की खेती की थी और उनकी मॉर्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम नहीं थी। अपने अफीम के खेत में मध्य प्रदेश का एक किसान। फाइल फोटो किसान चाहते हैं मार्फिन नहीं औसत उपज पर हो खेती किसानों को इसी मॉर्फिन उपज से एतराज है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तालुका में बालागूढ़ा गांव के किसान अमृतलाल पाटीदार गांव कनेक्शन को फोन पर बताते हैं, "अफीम की खेती में सरकार ने इतने नियम-कानून लाद दिए हैं कि ये किसान के बस की बात नहीं रही है। खेत में कितनी अफीम पैदा होगी ये किसान मेहनत और खाद-पानी डालकर ज्यादा कर सकता है, लेकिन उसमें मॉर्फिन कितनी निकलेगी ये कैसे तय करेगा। दूसरा मॉर्फिन सरकार की फैक्ट्री में तय होती है, अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता। जो अधिकारी लिख देते हैं, हमें मानना होता है। सरकार को चाहिए ये मॉर्फिन के नियम में बदलाव करें।" सरकारी अधिकारियों के मुताबिक नए नियम अफीम उत्पादन में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिए किए गए हैं। मंदसौर में ही तखतपुर गांव के किसान जितेंद्र सिंह कहते हैं, "ये बहुत जोखिम वाली खेती है। किसान डर-डर कर खेती करते हैं। मॉर्फिन का नियम पूरी तरह गलत है। मॉर्फिन, अफीम के अंदर पाया जाना वाला रसायन है वो किस खेत में किस जगह कितना निकलेगा ये प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारे यहां पिछले साल एक ही खेत में दो किसानों को पट्टे थे, और दोनों की मॉर्फिन काफी कम निकली थी। जब दोनों ने बराबर खाद-पानी दिया था।" अफीम की खेती में कमाई अमृतलाल पाटीदार के मुताबिक सरकार एक पात्र किसान को औसतन 12 आरी (0.12 हेक्टेयर) अफीम की खेती का पट्टा देती है। हमारे घर में दो पट्टे हैं। सरकार के नियमों के मुताबिक 9 किलो अफीम ले जाएंगी, जिससे मॉर्फिन निकलेगी तो 10 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अफीम के दाना (खसखस) बेचकर 12 आरी से करीब डेढ़ लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन इतने झंझट है कि पूछो मत। हम लोग अब अफीम की खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मान सम्मान की बात है।" क्या सम्मान से भी जुड़ी है खेती? अमृतलाल पाटीदार के मुताबिक एमपी हो या राजस्थान का ये इलाका जहां अफीम का पट्टा सम्मान से जुड़ा है। लोगों के पास जमीन कम हैं। ऐसे में जिसके पास पट्टा होता है उसे लोग सम्मानित मानते हैं। वो कहते हैं, "अफीम का पट्टा है तो बेटा-बेटियों की शादी-बारात में आसानी होती है लेकिन वर्ना यहां क्या रखा है।" एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 धारा का मुद्दा मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार को रोकने के लिए सरकार एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। एनडीपीएस एक्ट का प्रयोग अफीम या उससे जुड़े उत्पादों के व्यावसायिक मात्रा यानि खरीद-बिक्री के लिए उद्देश्य से नशीले पदार्थ रखने पर किया जाता है। इसके तहत 10-20 साल की सजा , एक लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कम मात्रा मिलने पर भी 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। संसद में एनडीपीएस एक्ट संशोधन अधिनियम 2020 (The Narcotic Drugs & Psychotropic Substances (Amend) Bill, 2021) पर चर्चा करते हुए 13 दिसंबर को हनुमान बेनीवाल ने देश में युवाओं के नशे में डूबने का मुद्दा तो उठाया ही साथ ही नारकोटिक्स विभाग द्वारा किसानों को गलत तरीके से फंसाए जाने, आपसी दुश्मनी का जरिया बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा, "किसान अगर किसी एनडीपीएस एक्ट के झूठे मामले में पकड़ा जाता है तो उसकी सुनवाई बहुत मुश्किल होती है। कई बार व्यक्तिगत कारणों से दुश्मनी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारी उनका शोषण करते हैं। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और वो किसी से फोन पर बात करता है भले उसका अपराध तस्करी से कोई लेना-देना न हो उसे पकड़ लिया जाता है। इसलिए धारा 8/29 के दुरुपयोग को लेकर सरकार को सोचना चाहिए सदन में मैं इस पर नियम 193 के तहत चर्चा की मांग करता हूं।" लोकसभा में एनडीपीएस एक्ट पर चर्चा करते हनुमान बेनिवाल मंदसौर के किसान मनोहर चौहान कहते हैं, "एमपी में मंदसौर नीमच, राजस्थान में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ समेत कई इलाकों की जेल युवाओं से भरी हैं, जो दाना पोस्ता के चक्कर में जेल गए हैं। जबकि उनमें मॉर्फिन की माला 0.2 फीसदी होती है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में डोडा-चूरा (अफीम का तना आदि) मादक पदार्थों में दर्ज है इसलिए पकड़ा जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा खेल ये होता है अगर कोई इस काम में पकड़ा गया तो वो जिसका-जिसका नाम ले लेगा सबको पकड़ा जाता है, फिर वहां लेन देन होता है। बहुत लोग दूसरी दुश्मनी निकालने के लिए इसका मिलीभगत कर इसका इस्तेमाल करते हैं।" क्या कहते हैं वकील मध्य प्रदेश की मंदसौर कोर्ट में अधिवक्ता महावीर प्रसाद बौराना कहते हैं, "एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले मादक पदार्थों (अफीम, डोडा-पोस्त, अल्प्राजोलम, गांजा आदि) के मामले में पुलिस जब किसी से रिकवर (जब्त) करती है करती है तो वो लिंक जोड़ती है, माल किससे लिया गया और किसे दिया गया, या जाना था, उसमें पुलिस उन्हें ऐसे लोगों को सहअभियुक्त बनाती है। सहअभियुक्त बनाने की धारा 8/29 है। अभी तक के हमारे अनुभव के मुताबिक 5 फीसदी ही मामले होते हैं 95 फीसदी फर्जी मुलजिम बनते हैं। एविडेंस की एक्ट की धारा 27 के तहत पुलिस मुख्य अभियुक्त (जो पकड़ा गया) उसके बयान के आधार पर धरपकड़ करती है।" वो आगे कहते हैं, "ये इतना संगीन मामला है कि हमारे मंदसौर जिले में ही 2-2 विशेष एनडीपीएस कोर्ट हैं (विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट)। जबकि नीमच में है, एक जावद में है। एक मनासा में है, एक जावला में है। ऐसे कई कोर्ट बनी हैं। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है।" वो आगे बताते हैं, "डोडा-चूरा में को एनडीपीएस एक्ट में शामिल कर रखा है। एनडीपीएस एक्ट में उस चीज को शामिल किया जाता है, जिसमें मॉर्फिन की मात्रा 0.04 फीसदी होना चाहिए लेकिन जबकि डोडा चूरा में 0.02 फीसदी ही मॉर्फिन है। किसान इसे एनडीपीएस एक्ट से हटाकर राज्य के आबकारी एक्ट में शामिल किया जाना चाहिए।इस आततायी कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे या तो बदला जाए या अफीम की खेती को राहत मिले।

खेती की लागत से कम है फसलों का बाजार मूल्य

लखनऊ। खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों के रेट में पिछले एक साल में 10-20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के बीच डीजल औसत 15-20 रुपए लीटर महंगा हुआ है। जबकि एनपीके उर्वरक की 50 किलो की बोरी 265 से 275 रुपए महंगी हुई है। जबकि साल 2022-23 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 40 रुपए प्रति कुंटल और पिछले साल (खरीद विपणन सीजन 2021-22) के लिए धान की एमएसपी में 72 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी हुई थी। जबकि इस दौरान कीट, रोग और खरपतवार नाशक दवाओं में 10-20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खेती की बढती लागत के अलावा किसान एमएसपी से कम रेट पर बिकती फसलों से भी परेशान हैं। यूपी के बरेली जिले में गेहूं में छिड़काव के लिए यूरिया लेने आए 19 साल के रामवीर कहते हैं, "खेती में ऐसा है कि एक कुंटल धान बेचकर एक बोरी (50 किलो) डीएपी नहीं खरीद सकते। बस काम चल रहा है। एमएसपी कुछ भी हो, हमने तो 1000 रुपए में धान बेचा था।" डीएपी की सरकारी कीमत 1206 रुपए है लेकिन कई जगह वो 1400-1600 में बिकती है। "खेती की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फसल के दाम उस तरह नहीं बढ़े। महंगाई का आलम ये है कि गन्ने की फसल में घास (खरपतवार) मारने की एक दवा आती है वो पिछले साल 170 रुपए की 100 ग्राम थी, इस साल 270 रुपए की हो गई है। जबकि गन्ने पर 5 साल में सिर्फ 25-35 रुपए प्रति कुंटल बढ़े हैं यानि 5 रुपया कुंटल। अब बाकी हिसाब आप लगा लो।" बिजनौर के बुजुर्ग किसान कुलवीर सिंह प्रधान खेती में बढ़ते खर्च का खाका समझाते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमानित आंकड़ों के मुबातिक कृषि सेक्टर और दूसरे सेक्टर की ग्रोथ। कृषि में 3.9 फीसदी की ग्रोथ, लेकिन दूसरे सेक्टर की रफ्तार तेज एक तरह जहां किसान खेती की लागत की महंगाई से परेशान हैं तो दूसरी आंकड़े भी बता रहे हैं कि खेती फिर घाटे का सौदा साबित हो रही है। 7 जनवरी 2022 में आए राष्ट्रीय आय के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में उत्साहजनक 3.9 फीसदी की ग्रोथ हुई लेकिन गैर कृषि क्षेत्र में औसत ग्रोथ 10 फीसदी के आसपास है। पिछले साल की अपेक्षा ये बढ़त अच्छी है, जिस पर सरकार अपनी पीठ भी थपथपा सकती है। राष्ट्रीय आय अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि सकल मूल्य बद्री घन (GVA) में अपस्फीतिकारक 5.2 फीसदी बढ़ेगा जबकि गैर-कृषि जीवीए लगभग दोगुनी दर से 10 फीसदी बढ़ेगा। गैर-कृषि जीवीए में उद्योग (इंडस्ट्री) और सेवाओं (सर्विस सेक्टर) को शामिल किया जाता है। गैर कृषि क्षेत्र में उच्च मुद्रास्फीति के कारण दो वर्ष बाद किसानों के लिए इस वर्ष खेती फिर नुकसानदायक साबित होने वाली है। बढ़ती लागत ने किसान का बजट बिगाड़ दिया। कृषि और दूसरे क्षेत्र के आंकड़ों के अंतर का सीधा सा मतलब है कि किसान ने खेती से जितना कुछ कमाया है, उससे ज्यादा वो डीजल-पेट्रोल, खाद, उर्वरक, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवा में खर्च रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)अहमदाबाद में प्रोफेसर और सेंटर ऑफ मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर (cma) के पूर्व चेयरमैन प्रो. सुखपाल सिंह के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कृषि सेक्टर में 3-4 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ नहीं है। ये ग्रोथ ठीक है बशर्ते बनी रहे। खेती की दूसरे सेक्टर से सीधा तुलना नहीं करना चाहिए। क्योंकि खेती बहुत जोखिम का और कुदरत का धंधा है। खाद्य महंगाई बढ़े या फिर किसानों की फसल की अच्छी कीमत मिले- प्रो. सुखपाल सिंह खेती में बढ़ती लागत और मुनाफे के सवाल पर प्रो. सुखपाल कहते हैं, "किसान की आय का मतलब है लागत निकालकर फसल बेचकर जो आमदनी हो। समस्या है इनपुट कास्ट काफी ज्यादा है। यही किसानों की लड़ाई है कि लागत बढ़ रही है और हमें जो मिल रहो है उससे किसानों का कोटा (हिसाब) पूरा नहीं हो रहा है। जब तक खाद्य पदार्थ की कीमतें नहीं बढ़ेगी किसान की आमदनी कैसी बढ़ेगी, उसका कोटा कैसे पूरा होगा। लेकिन समस्या ये है कि सरकार फूड इन्फ्लेशन की अनुमति नहीं देती, कीमतें बढ़ने पर इंपोर्ट शुरु जाता है।" खेती के घाटे को पूरा करने के लिए प्रो. सुखपाल सिंह कुछ उपाय भी सुझाते हैं। वो कहते हैं, "इसके 2 तरीके हैं या तो आप उसी खेती से ज्यादा उत्पादन करें, जो कम समय में संभव नहीं, क्योंकि देश में उस तरह के बीज,तकनीकी और एक्सटेंशन नहीं है। ऐसे में 2-3 चीजें बचती हैं। या तो आप खेत से ज्यादा माल निकला या फिर जो पैदा हो रहा है उसकी अच्छी कीमत लें, एक तरीका ये भी हैं कि हाई वैल्यू यानि ऐसे फसलें उगाएं जिनकी कीमत अच्छी है। लेकिन समस्या कई हैं। न खेत बढ़ सकते हैं न तुरंत सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा सकता है। एसे में मंडियां बहुत जरुरी है, मंडिय़आ ठीक जो जाएं। किसान तो पैदा करे उसकी कीमत मिल जाए तो काम ठीक हो जाएगा।" लेकिन समस्या यहीं आ जाती है, किसान के खेत से निकलते ही इन चीजों के दाम गिर जाते हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं धान पैदा होता है जिसका औसत रेट खुले बाजार में 1000-1500 के बीच रहा है। मध्य प्रदेश की मंदसौर मंडी में लहसुन और प्याज 50 पैसे किलो से लेकर 4 रुपए किलो तक बिका है। खबर लिखने के वक्त (2 फरवरी 2022) में महाराष्ट्र के धुले जिले में किसानों ने व्यापारियों को पपीता देना बंद दिया है क्योंकि व्यापारी किसान के खेत में 3 रुपए किलो का थोक रेट दे रहे जबकि किसानों के मुताबिक उनकी लागत ही 5-6 रुपए किलो की आती है। धुले जिले के किसान विकी राजपूत कहते हैं, "रेट इतना कम था कि किसानों ने कहा तोड़ाई नहीं करेंगे, व्यापारी वापस जा रहे हैं। पके फल खराब हो रहे हैं लेकिन उन्हें बेचकर भी तो घाटा ही हो रहा है।" फल और सब्जियों को नगदी फसलें माना जाता है। पिछले वर्षों में सरकार का जो फसल विविधीकरण के तहत ऐसे फसलों को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान धान-गेहूं के अलावा दूसरी फसलें उगाएं लेकिन कई जगह किसानों ने इसे आजमाया लेकिन बाजार जाने पर उन्हें निराशा हाथ लगी। यूपी में मक्का, हरियाणा में ज्वार-बाजरा, राजस्थान में मूंगफली समेत कई फसलों को लेकर कम खरीद और मंडियों से नकारात्मक खबरें आती रहती हैं। साल 2022-23 में कृषि सेक्टर के लिए आवंटित बजट धान गेहूं से आने वाली आमदनी घटी- एस महेंद्र देव मुंबई में स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (IGIDR) के निदेशक और कुलपति एस. महेंद्र देव के मुताबिक कृषि में व्यापार के लिए प्रतिकूल शर्तें मोटे तौर पर बताती हैं कि किसान की फसलों से होने वाली आमदनी के मुकाबले कृषि आदान (इनपुट) और स्वास्थ्य-शिक्षा पर खर्च ज्यादा हो रहा है। एस महेंद्र देव गांव कनेक्शन को फोन पर बताते हैं, "राष्ट्रीय आय के अनुमान के मुताबिक 2020-21 की कृषि ग्रोथ 3.6 से 3.9 है। इसमें फसल, पशुपालन और मत्स्य पालन के आंकड़े जुड़े हैं। अगर आप सिर्फ गेहूं धान और बागवानी जैसी फसलों का देखेंगे तो पाएंगे पशुपालन और मत्स्य आदि में बढ़त ज्यादा है। इसके अलावा मजदूरी से हिस्सा भी आमदनी की बढ़ा है। एनएसओ की रिपोर्ट भी बताती है कि किसान की आमदनी में फसलों से आने वाली आमदनी घटी है।" एस महेंद्र देव, केंद्र सरकार के कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। यह आयोग ही देश में फसलों की लागत तय करता है और आयोग की अनुशंसा पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। एस महेंद्र देव ने जिस मजदूरी की आमदनी का जिक्र किया है वो भी समझना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी बताते हैं कि किसान परिवार की आय में मजदूरी से होने वाली आय हिस्सा बढ़ा है। भारत जहां 67 फीसदी आबादी अभी गांवों में रहती है, वहां का एक बड़ी आबादी रोजगार और आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण और पारिवारिक बंटवारे में जमीन खेत बंट रही हैं। भारत में 42.6 फीसदी लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर- पाकिस्तान, चीन से बद्तर हालात संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 42.6 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं। पाकिस्तान में ये आंकड़ा 36.92, चीन में 25.33 फीसदी है। कनाडा में 1.51 फीसदी जबकि अमेरिका में महज 1.3 फीसदी लोग खेती से रोजगार चलाते हैं। यानि चीन, अमेरिका, कनाडा में सर्विस सेक्टर, मैन्यूफैक्चरिंग जैसे दूसरे क्षेत्रों ज्यादा लोगों के घर चल रहे हैं। अब किसान के बेटे की नौकरी लग रही होती है तो वो खेत बेच देता है। किसान पढ़ाई के लिए खेत बेच देते हैं। मजदूरी न मिलने से खेती से पलायन जारी है।"गांव से इसी तरह पलायन जारी रहा तो खेती और खाद्य सुरक्षा कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी।

ऋण गारंटी योजना ने दी बाजार को ताकत

(पेज 2 का शेष भाग)

में समस्त बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राशि का 40 प्रतिशत एवं अधिकतम 200 करोड़ रुपए की राशि तक उपलब्ध करा दिया गया था। इन इकाईयों को इस अतिरिक्त ऋणराशि को 2 वर्ष की मोरेटोरीयम अवधि को मिलाकर कुल 6 वर्षों में अदा करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान लागू किए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बहुत विपरीत रूप से प्रभावित हुए व्यापारियों एवं लघु उद्योग को बचाने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार ने उक्त योजना की घोषणा की थी। इस योजना के सफलता की कहानी उक्त वर्णित आंकड़े बयां कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों एवं सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों को इस योजना का बहुत अधिक लाभ मिला है। ऋण के रूप में प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता की राशि से इन उद्यमों को तबाह होने से बचा लिया गया है। इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक की अवधि तक ही उपलब्ध रहेगा। प्रारम्भ में तो यह योजना एमएसएमई इकाईयों के लिए प्रारम्भ की गई थी परंतु बाद में छोटे व्यापारियों एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली इकाईयों, आदि को भी इस योजना के दायरे में लाया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋणराशि की किश्तों को अदा करने के लिए एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि स्वीकृत की गई है अर्थात ऋण प्राप्त करने के एक वर्ष बाद ही ऋण के किश्तों की अदायगी प्रारम्भ होनी होती है एवं इसके बाद के तीन वर्षों में ब्याज सहित ऋण की अदायगी समान किश्तों में करनी होती है। अब छोटे छोटे व्यापारियों एवं एमएसएमई इकाईयों द्वारा यह मांग की जा रही है कि ब्याज सहित ऋण के किश्तों की अदायगी करने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इन इकाईयों के लिए अतिरिक्त कैश फ्लो तो बना नहीं है साथ ही किसी प्रकार की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी नहीं जोड़ी गई है, केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता को ही पुन: प्रारम्भ किया गया है। अत: बैंकों को छोटे व्यापारियों एवं एमएसएमई इकाईयों की इस मांग पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। उक्त योजना के लागू किए जाने से बैकों को भी लाभ हुआ है क्योंकि समस्त बैकों की गैर निष्पादनकारी आस्तियों में उक्त योजना के चलते बहुत कमी दृष्टिगोचर हुई है। उक्त योजना के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर लघु उद्योग एवं व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री मुद्रा ऋण योजना को अप्रेल 2015 में बैंकों के माध्यम से लागू किया गया था। उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों पर उधारकर्ता से प्रतिभूति नहीं ली जाती है अत: इस प्रकार के ऋण बैंकों से आसान शर्तों पर मिल जाते हैं। चूंकि आपात ऋण गारंटी योजना का कार्यकाल 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगा अत: इस योजना की सफलता को देखते हुए इसके अच्छे बिंदुओं को बैंकों में पिछले लगभग दो दशकों से चल रही इसी प्रकार की सीजीटीएमएसई योजना में शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में सीजीटीएमएसई योजना का लाभ विभिन्न बैंकों द्वारा अपने बहुत कम हितग्राहियों को दिया जा रहा है। अत: इस विषय पर बहुत गम्भीर चिंतन करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा चालू की जा रही इस प्रकार की योजनाएं यदि सभी बैंकों द्वारा अच्छे तरीके से लागू की जाती हैं तो छोटे व्यवसाईयों एवं एमएसएमई इकाईयों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने में आसानी होगी एवं इस प्रकार के ऋणों पर सरकार की अथवा सीजीटीएमएसई की गारंटी उपलब्ध रहेगी एवं बैंकों पर हितग्राहियों द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किए जाने के सम्बंध में जो लगातार दबाव बना रहता है, जिसके चलते कई बैंक तो छोटे छोटे व्यवसायियों को भी ऋण मिलना सरल हो जाएगा।

भारत की राजनीतिक दिशा तय करेंगे उपचुनाव के मुद्दे

(पेज 2 का शेष भाग)

मुख्यमंत्रियों के विपरीत। श्री आदित्यनाथ पहले ही श्री मोदी की छाया के बाहर खुद को स्थापित कर चुके हैं। कांग्रेस में, प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी उत्तर प्रदेश की रणनीति के प्रभारी हैं; और उन्होंने पंजाब में पार्टी अध्यक्ष के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू को चुना। पार्टी का प्रदर्शन उनके नेतृत्व कौशल को प्रतिबिंबित करेगा, और उनकी भूमिका पर आंतरिक बहस को प्रभावित करेगा।

परीक्षण में क्षेत्रीय राजनीति के दो मॉडल: उत्तर प्रदेश में सपा एक प्रभावशाली जाति के नेतृत्व वाली पिछड़ी राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है; पंजाब में शिरोमणि अकाली दल अल्पसंख्यक धार्मिक राजनीति करता है। भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक संरचनाओं के स्पेक्ट्रम में दो विशिष्ट मॉडल। दोनों एक संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पारंपरिक लामबंदी की रणनीतियाँ अब कमजोर हैं, और उनकी भ्रष्टाचार से ग्रस्त वंशवादी राजनीति मतदाताओं के लिए अस्वीकार्य है।

चौराहे पर दलित राजनीति कुछ साल पहले तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के दबदबे वाले गढ़ में दलित राजनीति दोराहे पर है। उत्तर प्रदेश में पहले भी कई बार सत्ता में रही बसपा का पतन होता दिख रहा है। पंजाब में भी इसकी मजबूत उपस्थिति थी, हालांकि इसने कभी सत्ता हासिल नहीं की। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा की कीमत पर दलितों के बीच महत्वपूर्ण पैठ बनाई है। पंजाब में, दलितों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया है, और पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी, एक दलित, को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के बाद उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन विधानसभा चुनावों के नतीजे कुछ संकेत दे सकते हैं कि यहां से दलित राजनीति कैसे विकसित होगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलितों के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

भाजपा के लिए गैर-कांग्रेसी विकल्प की महत्वाकांक्षाएं: दो मुख्यमंत्री हैं जो अपनी राजनीति को अपने-अपने मौजूदा कार्यक्षेत्र से बाहर परख रहे हैं – दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी। दोनों 2024 से पहले श्री मोदी के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में उभरना चाहते हैं। श्री केजरीवाल का ध्यान पंजाब है जहां उनकी पार्टी 2017 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी; सुश्री बनर्जी गोवा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आप गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी है; टीएमसी मणिपुर में खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही है। इन दोनों नेताओं की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं दो अलग-अलग मॉडलों और गणना के दो अलग-अलग सेटों पर आधारित हैं। इस बार उनका प्रदर्शन 2024 से पहले राष्ट्रीय राजनीति के पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा। जोदेश की दिशा तय करने वाला चुनाव होगा।

गन्ना किसानों की उम्मीद पर खरी उतर रही है योगी की भाजपा

बिजनौर/लखनऊ। लखनऊ से दिल्ली की ओर बढ़ने पर सीतापुर के बाद से गन्ने के ट्रक और ट्रालियां नजर आने लगती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बरेली पार करने के बाद इनकी संख्या बढ़ने लगती है, मुरादाबाद से लेकर रामपुर, हापुड़ और गाजियाबाद तक गन्ने से भरे ट्रक, ट्रालियां और बुग्गियां नजर आती हैं। गन्ना और ये ट्रैक्टर-ट्रालियां, बुग्गी ही इस इलाके की सामाजिक और राजनीतिक धुरी हैं। पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था और सियासत दोनों गन्ने के आसपास घूमती हैं। 7 चरणों में हो रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सबसे पहले पश्चिमी यूपी 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने के गढ़ पश्चिमी यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, हापुड़, गाजियाबाद, सहारनपुर, बड़ौत, मुरादाबाद से लेकर बरेली और तराई में लखीमपुर- गोंडा तक करीब 100 सीटे हैं जहां गन्ने का मुद्दा अहम हो सकता है। सरकार और किसान नेताओं की माने तो यूपी में 5 करोड़ किसान परिवार गन्ने की खेती से जुड़े हैं। अगर हर परिवार में 4-5 भी मतदाता भी हुए तो 2 करोड़ मतदाता गन्ना किसान के परिवारों से हैं, जिनके लिए गन्ना एक बड़ा मुद्दा है। "बिजनौर ही नहीं पूरे पश्चिमी यूपी के गन्ना बहुत बड़ा मुद्दा है। गन्ना का भुगतान बड़ी समस्या है। हमारी मिल नजीबाबाद (Kisan Sehkari Chini Mill) है। पिछले साल का गन्ना भुगतान नवंबर महीने में हुआ था। कम रेट और देरी से भुगतान यही मुद्दा है।" ढाकी साधो गांव के बुजुर्ग किसान चौधरी रामफल कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिजनौर गन्ने का सबसे बड़ा गढ़ बना है। उत्तराखंड से सटे तराई के इस जिले में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। निजी और प्राइवेट को मिलाकर 9 चीनी मिले हैं जबकि 10वीं के लिए तैयारी जारी है। किसान नेता दिगंबर सिंह कहते हैं, "बिजनौर की बात करूं तो तराई इलाका है, चारों तरफ गन्ना ही नजर आएगा। कुछ लोग खाने भर की गेहूं और सरसों उगाते हैं। कोई दूसरा उद्योग नहीं, गन्ने से ही घर चलता है तो गन्ना ही मुद्दा है। और सिर्फ यहीं नहीं पूरे पश्चिमी यूपी में गन्ना मुद्दा है। जरुरत है चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई जाए और किसानों को लागत के अनुसार दाम मिलें।" पश्चिमी यूपी के नब्ज को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौधरी कहते हैं, "गन्ने का पेमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सरकार कोई भी रही हो किसी ने 14 दिन में पेमेंट नहीं कराया। बीजेपी ने कहा था कि 14 दिन में कराएंगे तो लोगों को भरोसा हुआ और यही वजह रही थी कि बीजेपी को यहां प्रचंड जीत मिली थी लेकिन किसान फिर छला गया। उनका वादा भी पिछली सरकारों जैसा ही रहा।" हर पार्टी के लिए गन्ना किसान महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव(up election 2022) में गन्ना पश्चिमी यूपी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी का कोई चुनावी कार्यक्रम बिना गन्ने के पूरा नहीं होता है। बीजेपी सरकार गन्ना भुगतान की प्रक्रिया में आई तेजी और भुगतान के आंकड़े गिनाती है तो गठबंधन के सहारे चुनाव जीतने की जुगत में लगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी कई बार अपनी चुनानी बस में गन्ने के साथ नजर आ चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में गन्ने का रेट 400 करने का वादा कर प्रदेश के करीब 5 करोड़ किसान परिवारों के 2 करोड़ मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। गन्ना किसान और किसान आंदोलन पर टिका सपा और रालोद का गठनबंधन। फोटो- ट्वीटर सपा गन्ना भुगतान और गन्ना किसानों के मामले अपनी सरकार के कामकाज गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "बीएसपी और सपा के सरकार में 29 चीनी मिलें या तो बंद हुई थीं या औने-पौने दामों पर बेची गई थीं हमारी पांच साल की सरकार में 2 साल कोविड ने व्यवधान डाला बावजूद इसके कोई मिल बंद नहीं हुई। किसानों को अब तक 1 लाख 57 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। 3 नई मिलें लगाई हैं।" सीएम योगी आदित्यनाथ आगे कहते हैं, "चौधरी चरण सिंह

जो किसानों के मसीहा थे, उनकी कर्मभूमि छपरौली में रमाला चीनी मिल चालू हो चुकी है। बस्ती जिले के मुंडेरवा में जहां किसानों पर गोलियां चली थी वहां नई मिल चालू हो चुकी है। गोरखपुर की पिपराइच मिल भी नए सिरे सो चालू की गई है। इसके साथ 20 मिलों का आधुनिकीकरण पर राज्य सरकार काम कर रही है।" चुनावी घमासान के बीच पश्चिमी यूपी के किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वर्चुअल कार्यक्रम में कहा, "गन्ना किसानों का बकाया सालों-साल चलता रहा, योगी जी की सरकार ने बीते पांच सालों में पुराने बकाए सहित करीब 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है। पिछले सीजन का भी लगभग पूरा भुगतान हो चुका है और इस बार का भी बकाया तेजी से निपटाया जा रहा है।" लेकिन किसानों की समस्या सिर्फ बकाए तक नहीं है। समस्या गन्ने की खेती की बढ़ती लागत है। डीजल, उर्वरक और पेस्टीसाइड के मुकाबले गन्ने के रेट के बढ़े रेट बेहद कम है। केंद्र सरकार ने पिछले साल गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 5 रुपए कुंटल की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य समर्थन मूल्य (SAP) में 25 रुपए कुंटल की बढ़ोतरी की। यूपी ए ग्रेड गन्ने का मूल्य अब 350 रुपए कुंटल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इससे पहले 2017-18 में 10 रुपए की कुंटल की बढ़ोतरी की थी। वर्ष 2007 में बनी बसपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक गन्ने के रेट में कुल मिलाकर 115 रुपये का इजाफा किया था। अखिलेश यादव की सरकार में गन्ने का रेट 65 रुपये बढ़ा था। हालांकि दोनों ही सरकारों में मिलों में बंद, बेचे जाने और बकाए भुगतान का मुद्दा छाया रहा था। बिजनौर में श्योतरा गांव किसान कुलवीर सिंह प्रधान कहते हैं, "गन्ने में सबसे ज्यादा डीजल का खर्च है। डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए। यूपी में बिजली पूरे देश से महंगी है। गन्ने में घास खत्म करने के लिए एक दवा आती है, साल 2021 में 100 ग्राम की कीमत 170 रुपए थी जो 2022 में 270 रुपए की हो गई जबकि गन्ने के रेट में पिछले 5 वर्षों में 25-35 रुपए बढ़े हैं। इस पैसे में किसान क्या खाएगा, क्या खेती करेगा और क्या अपने बच्चों को पढाएगा।" मुरादाबाद के किसान राजवीर सिंह कहते हैं, "गन्ने का सबसे अच्छा रेट मायावती की सरकार में बढ़ा था, उस हिसाब से होते तो अब तक 400 हो जाते।" किसानों के मुताबिक उन्हें सबसे ज्यादा डीजल की महंगाई ने परेशान किया है। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2022 में डीजल की औसत कीमत 87 रुपए प्रति लीटर है। जबकि साल 2021 के जनवरी में रेट 74-75रुपए लीटर था। रबी के पीक सीजन में (नवंबर 2021) में किसानों को 98.89 रुपए में लीटर में डीजल खरीदना पड़ा। कई जगह से 100 का आंकड़ा पार भी कर गया था। थोड़ा और पीछे जाएं तो जनवरी 2020 में यूपी में डीजल की औसत कीमत 64-65 रुपए प्रति लीटर थी। भुगतान में हुए कई सकारात्मक बदलाव लेकिन 14 दिन का वादा आधूरा भुगतान के मामले में कई जिलों में मिलें 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही हैं तो कई जगहों पर (शामली में बजाज मिल) मिलों अभी पिछले साल का भी पैसा बाकी है। यूपी में बीजेपी में सत्ता में आने के बाद गन्ना किसानों को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। डिजिटल पर्ची से लेकर हाईटेक पेमेंट सिस्टम तक शामिल है। प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय भूषरेड्डी गांव कनेक्शन को बताते हैं, "प्रदेश में पहले चीनी मिलें चीनी बेचकर उस पैसे किसान का भुगतान न करके दूसरे काम में लगाती हैं। हम लोगों ने ऐसे एक नया सिस्टम लागू किया जिसमें चीनी, एथेनाल, बैगास का मिल कोई भी उत्पाद बेचे जाने पर उसका 85 फीसदी पैसा किसानों के भुगतान में जाएगा, बाकि मिल को मिलेगा। उससे काफी कुछ सुधार हुआ। भुगतान न करने वाले मिलों के खिलाफ नोटिस जारी कई गईं। 20 से ज्यादा मिलों पर कार्रवाई हुई है। अच्छा भुगतान करने वालों मिलों को न्यूनतम दरों पर साफ्ट लोन दिए गए ताकि किसानों को समय पर भुगतान हो सके। भुगतान प्रक्रिया अब सुचारु रुप से जारी है।" प्रदेश की चीनी मिलों ने पेराई सत्र 2021-22 में 25 जनवरी तक 465.26 लाख टन गन्ने की पेराई की थी, जिससे 45.67 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। किसानों के गन्ने की कीमत करीब 16000 करोड़ रुपए होती है। जिसमें से 9157.43 करोड़ का भुगतान हुआ था। अगर सिर्फ सरकारी क्षेत्र की मिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लखनऊ से मिले आंकड़ों के मुताबिक चालू पेराई सत्र 2021-22 के दौरान 3 फरवरी तक सहकारी क्षेत्र की 24 चीनी मिलों में 274868 किसानों ने गन्ने की आपूर्ति की, जिसमें 182097 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। इस सभी किसानों का कुल देय 1440.91 करोड़ रुपए था, जिसमें से 490 करोड़ का भुगतान हो चुका है। जबकि 950.91 अभी बाकी है। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा पिछले कुछ वर्षों में गन्ने के रेट न बढ़ने के पीछे सरकारों ने चीनी की कम खपत को रेट न बढ़ाने की वजह बताई। भारत से चीनी का निर्यात ज्यादा हो नहीं पाता क्योंकि ब्राजील समेत दूसरे देशों में प्रति किलो चीनी की लागत भारत से काफी कम है। ऐसे में सरकार ने कहा कि चीनी के अलावा गन्ने के बाई प्रोडेक्ट पर जोर देगी। जिसका एक बेहतर विकल्प एथेनाल बताया गया है। यूपी सरकार के मुताबिक बीजेपी सरकार में कुल 348 करोड़ लीटर का एथेनॉल का उत्पादन हुआ है जबकि बीएसपी के सरकार के दौरान 7-12 के बाद 58 करोड लीटर, सपा में 142 करोड लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ था। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है, जिले पेट्रोल में मिलाया जाता है। यह एक प्रकार से ग्रीन फ्यूल है,- जिसमें इस्तेमाल से हानिकाकर गैसों कार्बन मोनो ऑक्साइड और सल्फर डाईऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है। बजट 2022-23 में नरेंद्र मोदी सरकार ने गैर पर 2 फीसदी टैक्स लगाया है। चीनी मिलों के संगठन इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के मुताबिक 3 फरवरी को कहा कि चालू वित्त वर्ष केलिए संसोधित बजट अनुमान में चीनी उद्योग के लिए आवंटन बढ़ाकर 6,844 करोड़ रुपए किया गया जो स्वागत योग्य है। पहले यह4337 करोड़ था। इस्मा ने कहा कि यह गन्ना के भुगतान के निपटान की दिशा में सकारत्मक कदम है। एस्मा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए बजट आवंटन में 300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी (एथेनाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिलों को वित्तीय मदद) एथनॉल मिश्रण की बढ़ी आपूर्ति देश में तेल आयात के मद में होने वाले देश के खर्च को कम करेगी। चीनी का उत्पादन देश में चालू चीनी विपणन सीजन 2021-22 में अक्टूबर से जनवरी की अवधि में 5.64 फीसदी बढ़कर 1.87 करोड़ चन होने का अनुमान है जो पिछले साल समान अविधि में 1.77 करोड़ था। एस्मा के मुताबिक 31 जनवरी 2022 तक देश की 507 मिलों ने 187.08 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जो पिछले सीजन में 491 मिलों के 177.06 लाख टन से ज्यादा है। हालांकि इस दौरान चालू सीजन में देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादन राज्य में यूपी में चीनी उत्पादन पिछले साल के 54.4 लाख टन से घटकर 50.3 टन रहा है। हालांकि यूपी सरकार का कहना है कि 10 वर्ष (सपा बसपा) कार्यकाल में 64 लाख मीट्रिक टन चीनी का औसत सालाना उत्पादन होता था, जबकि बीजेपी सरकार के 5 साल में वार्षिक उत्पादन 116 लाख 71 हजार मीट्रिक टन का रहा है। उत्पादन और भविष्य की योजनाओं से परे किसानों को अपने आज की चिंता है। बिजनौर में शहर की सरकारी मिल पर गन्ना लेकर आकर किसान श्यो सिंह ने कहा, "किसान को समय पर पेमेंट नहीं मिलता। कर्जे लेकर खेती में लगाता रहता है। बनिया से पैसे लेता है। जो बाद में मिलों से रकम मिलती है वो बैंक और बनिया का ब्याज उतारने में चली जाती है।" गन्ने के मुद्दे पर पश्चिमी यूपी के कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार पाराशर कहते हैं, जैसे ही आप हरियाणा से यूपी में प्रवेश लेते हैं मुजफ्फरनगर-शामली से लेकर पूरा पश्चिमी यूपी और उधर शारदा-घाघरा की तराई गोंडा तक एक गन्ना बेल्ट है, ये जिले आपस में जुड़े हैं। गन्ने की राजनीति चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर अब तक है। उसके पीछे का बड़ा कारण है, कहने को गन्ना एक नगदी फसल है लेकिन असल में ये एक उधारी की फसल बनकर रह गई है। निजी हो या, सरकारी, अर्ध सरकारी, कॉ-परेटिव की मिलें किसान से गन्ना लेकर उसका साल-दो साल तक में भुगतान करती हैं।" वो आगे कहते हैं, "ये खेती के लिए धनी इलाका है। यहां साल में तीन फसलें होती हैं। किसानों को हर चौथे महीने, खाद, बिजली डीजल के लिए पैसे चाहिए होते हैँ। बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवा तक पैसे चाहिए। घर में शादी बारात होती हैं और पैसे नहीं होते फिर ये लोग कर्ज लेते हैं, जिसका ब्जाय देते हैं। लेकिन मिल बकाया पैसों पर ब्याज नहीं मिलता है। अगर किसान मिल की बजाए खांडसारी (क्रसर) आदि को गन्ना देता है है तो वहां सरकारी रेट से काफी कम रेट मिलता है। इसलिए वो परेशान रहता है। इसलिए गन्ना यहां मुद्दा है।" बंद पड़ी मिलों के कर्मचारियों और किसानों को मिल शुरु होने का इंतजार यूपी में पिछले कुछ दशकों में 38 चीनी मिलें बंद हुई हैं। सीतापुर जिले की महौली चीनी मिल घाटे के चलते 1998 में बंद कर दी गई थी। उस दौरान करीब मिल में 1000 से ज्यादा नियमित और संविदा कर्मी थे। हर चुनाव में इस मिल के शुरु होने की बाते होती हैं। लेकिन चुनाव के बाद मामला शांत हो जाता है। महोली इसी मिल परिसर में रह रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज मिश्रा कहते हैं, "हर चुनाव से पहले इस मिल की फिर चालू होने के की बातें और वादे होते लेकिन जीतने या हारने के बाद कोई सुध नहीं मिला। एशिया की सबसे जानी मानी चीनी मिल राजनैतिक शिकार हो गई। इससे इस क्षेत्र का बहुत विकास था। यहां का विकास थम गया है। कर्मचारी और क्षेत्रीय किसान दोनों चाहते हैं कि मिल चालू हो।" सरकारी आंकड़ों के मुताबिद देश में 756 चीनी मिल हैं, जिसमें से 250 बंद पड़ी हैं। बंद पड़ी मिलों में 38 मिल यूपी की है। सोर्स- लोकसभा लेकिन सिर्फ गन्ना ही चुनावी मुद्दा नहीं, मुद्दे और भी हैं हालांकि ये भी तय है कि पश्चिमी यूपी में इस बार के चुनाव की धुरी सिर्फ गन्ना नहीं है, उसके अलावा की मुद्दे हैं, जो चुनाव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करेंगे। किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी भी एक मुद्दा है। कई जगह किसान छुट्टा पशुओं से परेशान हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत में इस बार कानून व्यवस्था भी अहम मुद्दा है। तो जातीय समीकरणों की अपनी गुणा-गणित है। बरेली से लेकर बिजनौर तक बहुत सारे किसान ऐसे मिले जिन्होंने कम गन्ना रेट, गन्ना के बकाए को लेकर बीजेपी की सरकार को घेरा लेकिन कानून व्यवस्था पर सरकार के साथ नजर आए। बीजेपी सरकार ने सपा-बसपा का कार्यकाल का भी भुगतान किया है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मुद्दा है। यहां लोग अपराध कर गन्ने के खेतों में छिप जाते थे वो क्राइम कंट्रोल हुआ है। स्कूलों जाती लड़कियों से छेड़खानी होती थी वो कुछ हद तक कंट्रोल में अभी बिजली के कम किए है यो सब भी है। दूसरा सुबह मैं दिल्ली से आया दिल्ली-मुजफ्फनगर हाईवे से एक घंटे में मुजफ्फऱनगर था। वोट डालते वक्त ये सब विकास भी दिमाग में रहेगा।" वो आगे कहते हैं, "गन्ना हमारे यहां इतना ज्यादा है कि चीनी खप नहीं रही। तो इन्होंने इथेनॉल का विकल्प निकाला है, जिसपर इन्होंने (बीजेपी) सरकार ने काम किया है। गन्ना किसानों की समस्या है, लेकिन ये सब भी हैं, क्योंकि सुरक्षित रहोंगे तो सभी काम होंगे।"

देश के लिए बलिदान होने वाले
वीर सपूतों को शत्-शत् नमन।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

73वें
गणतंत्र दिवस
की प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएँ

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

जनभागीदारी से
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल. *aloksinghai67@gmail.com* सलाहकार संपादक:विपिन शर्मा,स्थानीय संपादक:संजय जैन।